Month End Market Prices of Fah ics

(Rs. per wtr.)

Texo Bosky 47"	*September 1987*
76x76(5-5 kgs.) printed	1410
Dyed	1500
China Bosky	
44x76(5.5 kgs.) .	12-00
44x76 (7.0 kgs.) .	15.00 -
Saree Cloth (49")	
60s (67/33)x76D Texturised 88x76	10-65

Loans for setting up industries

2467. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of FINANCE he pleased to state:

(a) the number of loans sanctioned by the Central Government to industrialists for setting up industries and factories during the last three years, State-wise, and the amounts sanctioned;

(b) the number of industries and factories set up by them during this period;

(c) the amount towards loan repaid by the loanees, State-wise, till October 1987; and

(d) the steps taken by Government to recover the loans' from those who have falied to repay the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POGJARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House to the extent availab'e and permissible under the rules.

ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के कतिपय विभागों में काम का बन्द होना।

2468. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री अजीत जोगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के प्रबंधकों ने मिल के कुछ विभागों में काम बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मजदूर कार्यमुक्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जियाजी काटन मिल्स लि०ग्वालियर ने मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसा आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 414 पुराने सादे करघों और अनुषंगी विभागों के कार्य चालन को निलम्बित करने के लिये औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अधीन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने इस आवेदन-पत्र का निपटान करते हुए मिल के प्रबन्ध-मण्डल को निर्देश दिये कि प्रभावित कामगारों के लिये एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना तैयार की जाये । स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना क्रियान्वित हो रही है । किसी भी कामगार को जबरन बेरोजगार नहीं किया गया है ।